which we have decided, so that they may not misuse because of their malfunctioning—the money which the public institutions have ivested in them ?

SHRI PRANAB MUKHERJEE ! far as the first part is concerned, I am afraid it is already affecting the climatc If there is so much of hullaballoo anb so much of resistance—after all people would like to make money, and not give charity or show petriotism. If they find that people are not interested, and that shares cannot be transferred, it will have its adverse effect. But I do hope that with the settlement of this issue, the position would be clarified. We are asking the various Investment Centre officers and others to make propaganda.

One point is quite clear : we are not going to abandon this scheme. It will continue. We are encouraging investment, and we would like to do so whatever be the pressure or otherwise.

In regard to the second point, I am not going to immediately appoint any committee ; but about the committee which I have appointed under the chairmanship of Mr. Narasimham, the terms of reference which I have given to them will cover some of the issues which the hon. Member has raised.

21.05 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Ban on Advertisement of Artificial Milk Food

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now we shall take up half-an-hour discussion.

श्री हरीकेश बहादुर (गोरखपुर) : एडवर्टिमेंट्स जो बेबी फूडज के बारे दिए जाते हैं उ पर बेन लगाने की बात को भारत समेत 120 देशों ने सिद्धांत रूप में स्वीकार किया हुआ है। डब्ल्यू० एच० ओ० की तरफ से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस में बहुत से देशों ने जिन में भारत भी शामिल है कहा था कि इनको बंद कर देना चाहिए। लेकिन हमारे देश ने फिर भी इस चीज को बन्द नहीं किया। चूंकि बन्द नहीं हुए इस वास्ते इसका एक बहुत बड़ा नुकसान खास तौर से छोटे बच्चों को होता है जो इसको पीते है और बहुतों की मृत्यु भी हो जाती है। जिन देशों ने इन एडवर्टिजमेंटस पर बैन लगाया है उन में कुछ हैं लेसोटो, नार्वे, स्वीडन, अल्जीरिया, मोजाम्बिक, श्रीलंका, तनजानिया आदि। न्यू गिनी ने कानून बनाया है कि बिना डाक्टर के नुस्खे के बेबी फूड लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन भारत सहमत होने के बावजूद भी इन एडवर्टिजमेंट्स पर बैन नहीं लगा रहा है।

प्रधान मंत्री ने अभी जेनेवा में एक वक्तव्य दिया था जिस को मैं नोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था :

> "Hard sell advertising and publicity makes us victims os habits which are ecnomically wasteful and wholly contrary to good health, Indira Gandhi on the marketing of baby foods, World Health Assembly, Geneva, May 1981.

फिलिपाइंज में इनको बन्द कर दिया गया है। उसका लाभ यह हुआ हैं कि बच्चों की जो मृत्यु हो जाती थी उस में 65 परसेंट की कमी आई हैं। साथ ही डायरिया में 71 परसेंट की कमी आई हैं। हमारे देश में रोक लगाने के बारे में सरकार के सामने क्या अड़चन आ रही है यह मैं जानना चाहता हूं।

वी० एस० शाह जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको मैं इंडिया टू डे से जो 15 मार्च 1983 का है, कोट करना चाहता हूं :

[श्री हरिकेश बहादुर]

"That his organisation would delete the picture of a smiling infant from the can. But a new can put a few months ago carries an even larger picture of a plump, smilling infant to counter the effect of the statement : "Mother's milk is best for the baby."

इन्होंने फैसला किया था कि हम हंसते हुए बच्चे का फोटो कैन पर नही लगाएंगे । उससे यह इम्प्रेशन मिलता था कि यह दूध पीने से बच्चे बहुत स्वस्थ होते हैं और जो कि गलत बात है बल्कि उससे हानि ही होती है, इस वास्ते उन्होंने यह बात कही थी । लेकिन क्या हुआ ? इसका उल्टा हुआ जब दूसरी बार बेबी फूड के कैन बनाए गए तो उससे भी बड़ी पिक्चर उन पर बनाई गई । डा० वर्गीज कुरियन जो चेयरमैन आफ गुजरात कोओप्रेटिव मिल्क मार्किटिंग फैड्रेशन हैं उन्होंने जब उन से पूछा गया कि शा ने ऐसा कहा था और उल्टा क्यों हुआ तो कहा :

"If Shah accepted this suggestion then he must have been weak. It was not our intention to stop putting the child's picture on the can... you don't expect me to put a picture of an elephant on a baby food tin."

उसी आर्गेनाइजेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर एक बात कहते हैं और चेयरमैन दूसरी एडवर्टिजमेंटस को बैन न करने से धीरे धीरे काफी नुकसान हो रहा है । यह स्थिति क्यों बनने दी जा रही है ?

गिफ्ट कमोडिटीज भी आ रही है, मिल्क पाउडर और बटर आयल भी बाहर से आ रहा है । इसको दूध के साथ मिलाया जाता है । मिल्क पाउडर जो यहां तैयार होता है, बेबी फूड जो यहां तैयार की जाती है, उसको इस में मिलाया जाता है ।

बेबी फूड में जो ऐड किया जाता है उससे हानि होती है क्योंकि यह पुराना भी होता है जिससे मिल्क फूड तैयार होता है । और टाइम लिमिट लिख देते हैं कि इतने साल तक काम कर सकता है, जब कि वह पहले ही पुराना होता है । सैम्पिल चैक नहीं किया जाता है ठीक से । एक बार मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया था कि तीन सालों में तीन बार सैम्पिल चैक हुए तो यह बहुत ही खतरनाक बात है और साथ ही जो आपका पी० एफ० ए० है उसके रूल्स के खिलाफ काम किये जा रहे हैं । लेकिन जो लोग इसको कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस प्रकार का काम करने वाले लोगों के खिलाफ जो कि आपके पी० एफ० ए० रूल्स को वायलेट कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही कर रहे हैं ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let us make history by concluding this half-an hour discussion within half-an-hour.

SHRI HARIKESH BAHADUR : I am concluding.

SHRI CHARANJIT YADAV : We can do it within fifteen minutes also.

श्री हरीकेश बहादुर : इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे जो पी० एफ० ए० रूल्स को वायलेट करके इन चीजों को मिला रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज मैंने पहली मर्तबा बहुत ही ऐक्टिव इस सदन के मैम्बर को बहुत ही लाचारी में कहते हुए सुना है। लेकिन जो डिस्कशन उन्होने मांगा है वह इम्पोर्टेन्ट हैं। यह बात सही है कि जो डब्लू० एच० ओ० और यूनीसेफ की मीटिंग हुई 1979 में उसमें उन्होंने प्रस्ताव किया जिसमें भारत भी शामिल था उन शुल्कों में जिन्होंने उसका समर्थन किया। और उसके बाद मिनिस्ट्री आफ सोशल वेलफैयर ने एक वर्किंग ग्रुप इस पर कायम किया जो इसको देखे। क्योंकि हमारे यहां न कोई इस तरह का कोड है काम्प्रीहैंसिव, न लेजिस्लेशन हैं जिसके तहत वेबी फूड पर कोई प्रतिबन्ध लगा सकें इसलिये एक वर्किन्ग ग्रुप बैठाया गया मिनिस्ट्री आफ सौशल बेलफैयर द्वारा जो इनडेप्थ स्टडी कर के सुझाव दे कि क्या करना चाहिये।

यह बात सही है कि बेबी फूड और इस का जिस तरह से ऐडवार्टिजमेंट होता है तो उससे ब्रैस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेन्स कम हो जाती है, जब कि बच्चों के लिये बहुत ही जरूरी है पहले चन्द महीनों में मां का दूध मिलना, क्योंकि उससे उसका सही डेवलमेंट और नरिशमेंट होता है और एक इमोशनल डैवलमेंट भी होता है। जिन बच्चों को मां का दूध नहीं मिलता उनमें बहुत से काम-प्लेक्स पैदा हो जाते हैं साथ ही इन्फेंट वार-टेलिटी और कई तरह की बच्चों की बीमा-रिया उनमें पैदा हो जाती हैं क्योंकि बेबी फूड में जो कंटेंट हैं वह मां के दूध का बदल नहीं हो सकता। लेकिन ऐडवर्टिजमेंट ऐसा होता है कि जैसे डिब्बे का दूध का बदल हैं। जो पढ़ी लिखी मातायें नहीं होती है वह उसको बनाकर देती हैं और सफाई का भी ख्याल नहीं रखा जाता है। तो इस तरह से बच्चों को दुगुना नुकसान होता है। इसलिये हमारा जोर है कि इस तरह के एडवर्टिजमेंट बन्द हों। मिनिस्ट्री आफ इन्फोर्मेशन ने रेडियो और टी० वी० पर ऐसे एडवर्टिजमेंट लेना बन्द कर दिया है और कहा गया है कि उनके कंट्रेक्ट्स रिन्यू न किये जायें और नए कंट्रेक्ट्स न लिये जायें।

इसमें तीन चीजों का ख्याल होता है। एक लेबलिंग का, दूसरे ऐडवर्टिजमेंट का... क्वालिटी का। इन तीनों चीजों पर ध्यान देते हुए हैल्थ मिनिस्ट्री, सोशल वेलफैयर डिपार्टमेंट और इन्फर्मेशन मिनिस्ट्री, तीनों मिलकर काफी जोर दे रही हैं और जल्दी ही इसका कुछ नतीजा निकलेगा। यह बात भी सही है कि कोड की जो इनकी रिकमेंडेशन थी, उनको हमारे यहां के वर्किंग ग्रुप ने मानने की बात भी कही है और इस बारे में जल्दी ही हमारी मिनिस्ट्री, ला मिनिस्ट्री से सलाह करेगी और जैसे ही सारी चीजें तैयार होंगी आपके सामने आयेंगी। हमारी भी कोशिश होगी कि यह एडवर्टाइजमेंट जल्द से जल्द बन्द होने चाहिए। इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इनकी रिकमैंडे-शन पर पूरी तरह से विचार हो रहा है और हमारी मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट आफ इंडिया भी इसकी तरफ अधिक ध्यान देगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपा-ध्यक्ष महोदय, आधे घंटे की बहस में जो सवाल उठाया गया है, मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहिबा के जबाब से यह ज्यादा गंभीर बन गया है। इन्होंने 2, 3 चीजें स्वीकार की हैं।

पहला इनका कहना है कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान मुल्क में हो रहा है, इससे इनकी मिनिस्ट्री और सरकार वाकिफयत

[श्री चन्द्रजीत यादव]

रखती है। दूसरा कहना है कि गलत तरीके से विज्ञापन हो रहें हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : You know that the Minister to reply is also a mother.

SHRI CHARANJIT YADAV : I appreciat her concern as a mother.

इन्होंने इस बात को तसलीम किया है कि जो विज्ञापन निकलते हैं उससे लगता है कि मां के दूध के बदले में उतनी ही इसकी खूमासियत है, यह अच्छा है। इस तरीके से लोगों को गुमराह किया जाता है, यह भी एतराज की बात है।

तीसरे इन्होंने यह कहा कि इसके बनाने में पूरी सफाई का और दूसरी चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता है इससे हमारे बच्चों पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ता है।

जब खुद इन तमाम बातों को इन्होंने तसलीम कर लिया कि इस तरह की बातें हमारे बच्चों के साथ हो रही हैं, जिन पर देश का भविष्य निर्भर करता है, जिसका डबलू० एच० ओ० और यूनिसेफ ने अन्तर्राष्ट्रीय फोरम पर तसलीम किया है, इसके बाद भी 3 साल लग गये, यह अपने आप में अपराध है। यह साबित करता है कि सरकार की मशीनरी कैसे फक्शन करती है इतने बड़े सवाल पर, जिसका बच्चों से सीधा सम्बन्ध है। 3 साल हो गये सरकार इसे रोक नहीं पाई है। मैं समझता हूं कि यह सरकार पर बहुत बड़ा आरोप है, सरकार की इसमें हिस्सेदारी है।

क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार महज अपनी इच्छा ही नहीं, बल्कि क्या यह कहेगी कि हमारी कोशिश होगी, और क्या वह अगले सेशन में कोई कानून बनाने के लिये बिल यहां पेश करेगी कि इस तरह के विज्ञापन, जिसको सरकार गलत समझती है, उसको रोक दिया जाये ताकि हमारे बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ न हो सके? जब तक यह कानून नहीं बनता है, तब तक और कौन से प्रभावकारी कदम सरकार उठाने जा रही है, जिससे बच्चों का नुकसान न हो सके?

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सवाल को देखने से स्पष्ट होता है कि इसमें दो मुद्दे उठाये गये हैं और दोनों के अलग-अलग जबाव दिये गये हैं। मैं उसे पढ़ देना मुनासिब समझता हूं इससे मंत्री जी को जबाब देने में आसानी हो जायेगी।

"(1) कृत्रिम दुग्ध आहार से मरने वाले बच्चों की संख्या के बारे में कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तथापि, यह देखा गया है कि जिन बच्चों को बोतल से दूध पिलाया जाता है उन्हें अतिसार सम्बन्धी रोग और श्वसन तन्त्र के संक्रमण हो जाने का खतरा अधिक होता है।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर बच्ची को बोतल से दूध पिलाने सम्बन्धी विज्ञापनों पर पहले से प्रतिबन्ध लगा दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों। संघ शासित क्षेत्रों को ये हिदायतें जारी कर दी हैं... इत्यादि।

कृत्रिम दूध से लाखों बच्चों की मौतें हुई हैं। सवाल में कहा गया है कि लगभग दस लाख मौतें प्रति-वर्ष होती हैं। परन्तु मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि कितनी मौतें हुई हैं। उन्होंने गोल-मोल ढंग से जबाब दे दिया है। सरकार ने इस मामले की छान-बीन की है और इसकी गंभीरता को समझा है और कहा है कि हम इसके प्रचार पर रोक लगाएंगे। अगर सरकार ने इसकी गंभीरता को समझा न होता, तो मंत्री महोदय जल्दी यह बात कहने के लिए तैयार न होते।

मुझे बताया गया है कि पहले व्यावसायिक आधार पर बाहर से मिल्क पाउडर मंगाया जाता था। इसके बंद होने पर गिफ्ट के रूप में मिल्क पाउडर और मक्खन आ रहे हैं। जब ये चीजें बाहर से गिफ्ट के रूप में आती हैं और गरीबों के लिए आती हैं, तो क्या सरकार ने पता लगाया है कि क्या किसी गरीब बच्चे को मिल्क या मक्खन दिया गया है, अगर दिया गया है, तो कौन से माध्यमों से दिया गया है और अगर नहीं दिया गया है, तो ये चीजें कहां गई हैं? क्या यह सही है कि यह मिल्क पाउडर बड़े बड़े डेयरी फार्म्ज को दे दिया गया है और उन्होंने उसको बेचा है ? जब मुफ्त में आया, तो उसे बेचा क्यों गया ? मेरी जानकारी है कि उन फार्म्ज द्वारा अपने यहां का 20, 25 प्रतिशत दूध और बाकी का यह मिल्क पाउडर — जो तीन चार साल पड़ा रहता है — मिला कर सुखाया जाता है, उसे नये डिब्बों में पैक किया जाता है और मैनुफैक्चर तथा एक्सपाइरी की डेट बदल दी गई है। यही मिल्क पाउडर बच्चों को हानि पहुंचाता है। क्या मंत्री महोदय यह पता लगाएंगी कि किन किन फैक्टरियों को यह मिल्क पाउडर दिया गया और उन्होंने क्यों इसमें मिलावट की और इसको एक पोष्टिक आहार के बजाए जहर बना दिया ? क्या मंत्री महोदय उनको कोई सजा देंगी ?

अगर यह बेबी फूड बाहर से मंगाना बद कर दिया जाए, तो सरकार उसके स्थान पर क्या व्यवस्था करेगी ? वास्तव में यह बेबी फूड वगैरह सब शहरी बच्चों के लिए है। गांवों के बच्चों के लिए अभी तक अच्छा दूध, रस या जूस देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जब यह बेबी फूड नुकसान कर रहा है और इसके कारण लाखों बच्चे मर रहे हैं, को सरकार शहरी बच्चों को कौन सा पोष्टिक आहार देगी, या केवल मां के स्तन-पान से जीवित रह सकेंगे ? यदि इस बारे में कठिनाई होती है, तो बच्चों के लिए बकरी, गाय और भैंस का ताजा दूध मुहैया कराने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

मेरा अपना ख्याल है कि जब तक गांवों में गरीब व्यक्तियों के दरवाजे पर दुधारू पशु आप नहीं बंधवा पायेंगे तब तक गांवों के करोड़ों बच्चों को आप कोई पौष्टिक आहार नहीं दे पायेंगे, शहरों में चन्द बच्चों को आप बेबी फूड वगैरह दे दें। तो मैं जानना चाहूंगा कि देहात के उन करोड़ों बच्चों के लिए आपकी क्या योजना है ? दूसरी बात यह है कि अभी एक गाय जो आधा या एक किलो दूध देती है वही सभी दरवाजों पर बंधी रहेगी या उनकी नस्ल सुधार के लिए भी सरकार कुछ विचार कर रही है यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे पहले विदेशों से आप खरीदकर मंगवाते थे और अब भीख में आ रहा है, उनके ऊपर ही आप निर्भर करते रहेंगे।

SHRI KUSUMA KRISHNA MURTHY (Amalapuram) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am glad that the Government has realised the importance of banning requirements about artificial milk foods because every year one million babies die in the developing countries. India is one amongst them.

Sir, just now the Minister stated that she gave instructions to ban the advertisements on the radio and television. I do not know whether they have excluded newspapers because even till today radio and TV are confined to a limited population; the mass media is newspapers. Apart from this, I do not think the Indian women by and large need education to feed their children with their own milk. The India women are held in high esteem because they secrific a lot for their children and therefore, unless they do not have their own milk, generally they try to feed their children with their own milk. When I go through all these things, it is quite amusing for me to know that when we want to build a healthy child, the Government is concentrating on limiting the babies and also banning advertisements adout artificial milk foods. I do not think it is a solution at all for having a healthy baby. First of all, the Government has to concentrate on producing good and adequate baby food and they must also see that they are properly distributed. Actually, the advanced countries instead of restrseting the advertisements, advertise in a massive way about foodstuff required for men, women and children and also animals, Therefore, the Government have to concentrate on the production of good and adequate foodstuffs instead of banning the arteficial milk foods. If it is really harmfull, they may also stop it, but that is not a solution. The real solution lies in taking proper care to see that necessary and adequate baby foods are produced and if necessary, they should be widely advertised in order to help the people to know that adequate baby food is available in this country. This would solve the problem. Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether she has any problems in regard to this.

श्रीमती मोहसिना किदवई : अध्यक्ष महोदय, पहले तो चन्द्रजीत यादव जी ने जो बात कही है उसको मैं साफ कर दूं । राही साहब ने भी कहा कि बहुत से बच्चे इस कारण मर रहे हैं लेकिन यह बात बिल्कुल ही गलत है । मैंने अपने जवाब में यह कहीं नहीं कहा है कि दूध के कारण बच्चे मर रहे हैं । यह एडवर्टीजमेन्ट्स बन्द होने की जो बात है यह सिर्फ इसलिए है कि मां का दूध जो बच्चों को मिलता है उससे वे वंचित न रहें । मायें इस लोभ में आयें कि ऊपर का बोतल का दूध पिलाना ज्यादा फायदेमन्द है । इसके पीछे भावना यही है कि ब्रेस्ट फीडिंग का प्रचार प्रसार बढ़े । बच्चों को मां का दूध अच्छी मिकदार में मिले, ताकि वे बच्चे तंदरुस्त हों और एक अच्छे नेशन में रहने के काबिल बनें और नेशन को बनाने के काबिल बनें । दूसरी बात जैसा कि श्री चद्रजीत जी ने कहा ..

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mother do not want to breast feed their own children. They want to give powder milk.

श्री मोहसिना किदवई : यह बहुत गलत बात है । कहीं-कहीं ऐसी बात होती है । अभी राही जी ने गाँव के बच्चों की बात कही, मैं उनसे कहना चाहती हूं कि यह पौष्टिक आहार की बात नहीं है, डिब्बे की दूध की बात है । उसका एडवर्टिजमेंट बंद होना चाहिए और बच्चों को मां का दूध ज्यादा मिलना चाहिए । जैसा कि चन्द्रजीत जी ने कहा कि हम क्या कदम उठा रहे हैं ? यह बात सही है कि अभी कोई लैजिसलेशन नहीं बना है, लेकिन लॉ-मिनिस्ट्री जल्दी ही कोई

लैजिसलेशन बनाएगी, जिससे हम इन चीजों को रोक सकेंगे। हमारा विचार यह है कि ··

श्री राम लाल राही : बच्चा मां के स्तन से दूध कितने साल पिएगा और उसके बाद क्या पिएगा ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : इस वक्त मां के दूध और डिब्बों के दूध की बात हो रही है।

श्री राम लाल राही : बच्चा माँ का दूध एक साल, दो साल तक पीता है। डिब्बे का दूध तीन-चार-पाँच साल तक वही पीता है, क्या तब खराब नहीं होता है ?···(**व्यवधान**)···

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : राही जी न आपने पीया और न मैंने पीया, क्यों झगड़ा करते हो।

श्रीमती मोहसिना किदवई : प्रपोजल यह है कि पी०एफ०ए० के रूल को अमेंड किया जाए, ताकि उसके जरिए हम काबू पा सकें। गवर्नमेंट के मीडिया रेडियो और टेलीविजन पर एडवर्टिजमेंट बंद कर दिए हैं। जहां तक न्यूज पेपर की बात है, न्यूज पेपर्स में बहुत सी प्राइवेट एजेंसियां हैं, उसके लिए हमें ला मिनिस्ट्री से राय लेनी पड़ेगी। जब उनकी राय आ जाएगी, तब हम उनके लिए कदम उठा सकेंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन्स दी हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा माताओं को शिक्षित करें कि ब्रैस्ट फीडिंग बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर है। जब तक हम उनके ऊपर कोई प्रतिबंध कानूनी तौर पर न लगा सकें, तब तक के लिए डिब्बों में जो दूध आता है, उस पर आई० एस० आई० का मार्क जरूर होना चाहिए। इन्ग्रेडिएंट्स की लिस्ट भी जरूर ऊपर होनी चाहिए। अभी आपने कहा कि जो पाउडर्ड मिल्क बाहर से आता है, उसको मिलाकर बनाते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होता है। यदि आपके पास कोई स्पैसिफिक वाक्या हो तो आप हमें बताइए कि इतना दूध बनाया हैं और डिब्बों का दूध खराब हुआ है। तब हम इसकी कुछ रोकथाम कर सकेंगे। लेकिन जनरल-वे में तो बहुत मुश्किल है। आपने यह भी कहा कि सैम्पल नहीं लिए जाते हैं। बहुत सी स्टेट्स में सैकड़ों की तादाद में दूध की सैम्पल्स लिए गए हैं। कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमें भी दायर किए गए है। ऐसी बात नहीं हैं कि हम सतर्क न हों। दूसरी बात यह कि सोशियल वैलफेयर मिनिस्ट्री भी इनटच है। हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से भी इसके मुताल्लिक काम होता है। राही साहब ने कहा कि लाखों बच्चे मर गए हैं, ऐसी कोई फीगर हमारे पास नहीं है। डिब्बों का दूध पीकर कितने लाख बच्चे मर गए हैं। दुनिया में हिन्दुस्तान का इन्फैंट मोटेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। इसका कारण यह नहीं है कि बच्चे ऊपर का दूध पीकर मरते हैं। मदर मिल्क ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मिल सके, उसके लिए जरूरी है कि हम टाप फिडिंग कम कर सकें। ऊपर का दूध देना ही है तो भैंस, गाय, बकरी आदि का ताजा दूध बच्चों को दें, न कि बच्चों को डिब्बों का दूध दिया जाए। हमारी कोशिश यही है कि बच्चों की हैल्थ बनें। जाहिर बात है कि बच्चे किसी भी नेशन की दौलत होते हैं। उस दौलत को और सही ढंग से आगे बढ़ाने में हम सब का इन्टरैस्ट है। मिल्क पाउडर के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के लिए कहा गया था। यह बिल्कुल बैसलैस बात है कि हमारे यहां जो मिल्क पाउडर आता हे वह अब फूड

[श्रीमती मोहसिना किदवई]

मैन्युफेक्चर्स को दिया जा रहा है। कहीं से जो भी गिफ्ट पाउडर आता है वह 1982-83 में किसी बेबी फूड मैन्युफैक्चर्स को नहीं दिया गया। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जो फ्लड के जमाने में आया था वह मिसयूज नहीं हुआ और न ही किसी कम्पनी को दिया गया।

MR. DEPUTY-SPEAER : Now, the House stands adjourned to re-assemble tomorrow at 11.00 a.m.

21.36 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 25, 1983/Bhadra 3, 1905 (Saka).

———